13. डा० भगत सिंह,
निदेशक (राजभाषा), कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।

14. मंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, (भा०कृ०अ०प० शाखा)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एक दल द्वारा बिहार में रबी की फसल का प्रदर्शन

2189. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के दल ने मुंगेर में रबी की फसल का एक प्रदर्शन आरम्भ करने के पश्चात् हाल में गंगा के क्षेत्र की भूमि की जांच करायी थी और क्या वहां फसल की बोआई, खाद डालने तथा भूमि की सिंचाई का काम इस परीक्षण के अनुसार किया गया था ;

(ख) क्या मुंगेर कृषि विज्ञान केन्द्र और राज्य सरकार के कृषि विभाग ने इसमें अपना सहयोग दिया था कि उन्होंने इस संबंध में इस दल से सहायता प्राप्त की थी; और

(ग) क्या उपर्युक्त विषय में इससे पूर्व कोई योजना बनाई गयी थी यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और भविष्य में क्या किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) जी हां, श्रीमन् भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के परिचालन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले गंगा दियारा की मिट्टियों की जांच की गयी जब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, रबी की फसलें बोई गयीं और खाद और सिंचाई के उपयुक्त स्तरों की किसानों के लिए सिफारिश की गयी। इन स्तरों को प्रयोग में लाना उनके श्रोतों और निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ख) जी हां, श्रीमन्। कृषि विज्ञान केन्द्र, मुंगेर और राज्य सरकार के कृषि विभाग ने इस सम्बन्ध में अपना सहयोग प्रदान किया है।

(ग) जी हां, श्रीमन्। रबी के प्रदर्शन और क्षेत्र दिवसों को आयोजित करने के लिए प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना तैयार की गयी थी। सदर और जमालपुर विकास खण्डों के आठ गांवों में नवीनतम प्रौद्योगिकियों और प्रबंध पद्धतियों से युक्त 900 प्रदर्शन किये गये जिनमें गेहूं, चना, सरसों और मक्का का 500 एकड़ क्षेत्र शामिल था। आने वाले खरीफ 1987 के मौसम में इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई०ई०जेड०) में विदेशी जहाजों द्वारा मछलियों का पकड़ा जाना

2190. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछलियां पकड़ने के लिए विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित किए जाने के संबंध में सरकार ने हाल में क्या नीति अपनाई है ; और

(ख) इस नीति से देश के लाखों मछुआरों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) जनवरी, 1987 में घोषित की गई नई नीति के अन्तर्गत, भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के

लिए विदेशी कम्पनियों को आमन्त्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है । तथापि, इस नीति में भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में प्रचालन के लिए भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी स्रोतों से मत्स्यन जलयान को चार्टर किये जाने की व्यवस्था है।

(ख) भारतीय मछुआरों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चार्टर किये गये विदेशी मत्स्यन जलयानों को सामान्य नियम के अनुसार पूर्वी तट से 12 नाविक मील परे और पश्चिमी तट से 24 नाविक मील परे प्रचालन की अनुमति दी जाएगी । इसके अतिरिक्त, चार्टर किये गये विदेशी मत्स्यन जलयानों को दोनों तटों में कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रचालन की अनुमति नहीं है।

Water problem in Rajasthan

2191. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government had recently received representations from the Government of Rajasthan, and from M.Ps. and some organisations for assistance to solve the water problem in rural areas of Rajasthan; and

(b) if so, the details thereof and the nature and extent of assistance being given by the Central Government to solve the problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) Matters pertaining to clearance of schemes under Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) and additional allocations were raised in these letters. In 1986-87, Rs. 27 crores and in 1987-88, so far Rs. 8.19 crores have been released by the Central Government to the Government of Rajasthan for implementing scheme under ARWSP. Rs. 2.06 crores have been released in 1986-87 for the Mini Mission (Project Area) of Barmer district for undertaking activities under the Technology Mission on Drinking Water in Villages and Related Water Management. Under drought assistance, Rs. 13.81 crores in 1986-87 and Rs. 8.79 crores in 1987-88 have been provided to the State for the Rural Water Supply Sector.

दिल्ली प्रशासन के खाद्य विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2192. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या है सच है कि सरकार को गत छः महीनों के दौरान दिल्ली प्रशासन के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के गांधी नगर, के मण्डल संख्या 3 के वर्तमान मण्डल अधिकारी और मण्डल सं० 2, रघुवरपुरा के निरीक्षक के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डल अधिकारी और निरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां, सर्किल संख्या 3, जिसके क्षेत्राधिकार में रघुवरपुरा क्षेत्र आता है, के खाद्य और आपूर्ति अधिकारी तथा सर्किल संख्या 3 (सर्किल संख्या 2 नहीं) के क्षेत्रीय निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) इस बारे में विस्तृत जांच की गई है और संबंधित क्षेत्रीय निरीक्षक का तबादला कर दिया गया है। खाद्य और आपूर्ति अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें प्रमाणित नहीं की जा सकी।